

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा-5/2010पार्ट

जयपुर, दिनांक: 11-10-12

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- आरटीई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाप्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) के निर्धारित बायत।

संदर्भ:- शिविरा/प्रार/आरटीई./यूनिट कॉर्स/12-13/19626/138
दिनांक 29.8.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाप्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्मरण प्रतिबालक व्यय रूपये 8748/- (अक्षरे नौ हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) प्रतिवर्ष अथवा विद्यालय द्वारा प्रतिबालक ली जा रही फीस, जो भी कम हो, के किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

01. यह यूनिट कॉर्स 2012-13 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ट किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने नियत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।
04. इस यूनिट कॉर्स में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे रामस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित भाने जायेंगे।
05. इस यूनिट कॉर्स में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन भण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू-आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त वा उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्मरण देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.ली संख्या 101203850 दिनांक 8.10.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

मवदीय,


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा० शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, आयोजना, जनशविल विभाग।
10. उप शासन सचिव, आयोजना, जनशविल विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
12. वित्तीय सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
13. राष्ट्रीय पत्रावली।


शासन उप सचिव 11/10

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा-5/2010पाट
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

जयपुर, दिनांक: 19-07-2013

विषय:-आरटीई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013-14 के निर्धारण जावत।
संदर्भ:-शिविरा/प्रारं/आरटीई./सी/यूनिट कॉर्स्ट/18882/13-14/लूज 8/
दिनांक 28.6.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानान्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 11704/- (अक्षरे चारह हजार सात सौ चार रु. मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

D.C.(RTE)

28/1
25.7.13

10/15

01. यह यूनिट कॉर्स्ट सत्र 2013-14 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ट किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियन्त्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का उचित सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जाने सुनिश्चित किया जायेगा।
04. इस यूनिट कॉर्स्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेंगे।
05. इस यूनिट कॉर्स्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर ग्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू-आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

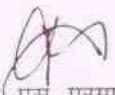
यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आईडी. संख्या 101303193 दिनांक 18.7.

2013 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा० शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, सर्वेशिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, सरस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
10. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग।
11. उप शासन सचिव, आयोजना, जनशक्ति विभाग।
12. वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
13. वित्तीय सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।


(दी. एस. परमार)
संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
School Education Department

E.21(19)Edu.-I/E.E./2009

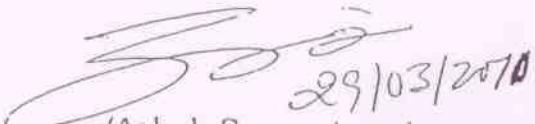
Jaipur, the 29th March, 2011

-NOTIFICATION-

In pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to disadvantaged group", namely:-

- a) the Scheduled Castes,
- b) the Scheduled Tribes,
- c) Other Backward Classes and Special Backward Classes whose parents' annual income does not exceed ₹. 2.50 lacs, and
- d) a child covered under the definition of "person with disability" under clause (t) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

By Order of the Governor,

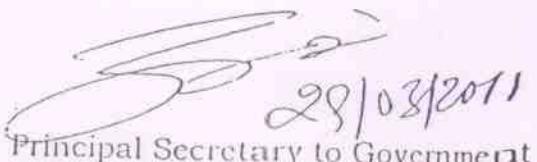


29/03/2011

(Ashok Sampatram)
Principal Secretary to Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Education Minister, Rajasthan, Jaipur
3. P.S to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
4. Director Printing and Stationary Department (along with additional copies) for publication of the Notification in the Rajasthan Gazette dated 29/03/2011.
5. Director, Public Relations, Rajasthan, Jaipur



28/03/2011

Principal Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009

Jaipur, the 29th March, 2011

-NOTIFICATION-

In pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to weaker section", namely:-

- a) A child whose parents are included in the list of Below Poverty Line families (both Central and State lists) prepared by the Rural Development Department / Urban Development Department of the State Government, and
- b) A child whose parents' annual income does not exceed ₹. 2.50 lacs.

By Order of the Governor,



28/03/2011

(Ashok Sampratram)
Principal Secretary to Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Education Minister, Rajasthan, Jaipur
3. P.S to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
4. Director Printing and Stationary Department (along with additional copies) for publication of the Notification in the Rajasthan Gazette dated 29/03/2011.
5. Director, Public Relations, Rajasthan, Jaipur



29/03/2011

Principal Secretary to Government